सम्पादकीय

पेशावर का अमेरिकी दूतावास बंद बदलती कूटनीति का संकेत

अमेरिका द्वारा पेशावर स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय महज प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय हालात का एक महत्वपूर्ण संकेत है। आधिकारिक तौर पर अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से जोड़ा है, लेकिन इसके पीछे की व्यापक रणनीतिक परतें कहीं अधिक गहरी हैं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों का केंद्र रहा है। अफगानिस्तान की सीमा से सटा यह इलाका आतंकवाद, उग्रवाद और अस्थिरता से जूझता रहा है। ऐसे में अमेरिका का यह कदम इस बात की पुष्टि करता है कि जमीनी हालात अभी भी उसके लिए भरोसेमंद नहीं हैं। खासतौर पर हाल के घटनाक्रम जैसे ईरान-अमेरिका तनाव 2026 के बाद क्षेत्र में बढ़ी अस्थिरता, ने अमेरिकी चिंताओं को और गहरा किया है। दूतावास बंद करने का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। बल्कि उसने स्पष्ट किया है कि इस्लामाबाद स्थित दूतावास के जरिए वह अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को जारी रखेगा। यह बदलाव 'फिजिकल प्रेजेंस' से 'सेंट्रलाइज्ड डिप्लोमेसी' की ओर संकेत करता है, जहां कम जोखिम वाले स्थानों से संचालन को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि, इस फैसले के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। यह पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा तंत्र पर एक अप्रत्यक्ष सवाल खड़ा करता है। यदि एक प्रमुख वैश्विक शक्ति अपने राजनयिक ठिकानों को सुरक्षित नहीं मानती, तो यह अंतरराष्ट्रीय निवेश और भरोसे पर भी असर डाल सकता है। कराची और लाहौर में हालिया हिंसक घटनाएं इस आशंका को और पुष्ट करती हैं। इसके साथ ही, अमेरिका का यह कदम उसकी वैश्विक रणनीति में बदलाव को भी दर्शाता है। अब वह जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष मौजूदगी घटाकर तकनीक, साझेदारी और दूरस्थ कूटनीति पर अधिक जोर दे रहा है। यह मॉडल भविष्य में अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। भारत के दृष्टिकोण से भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण में किसी भी बदलाव का असर दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ता है। यदि पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता बढ़ती है, तो उसका प्रभाव सीमापार सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। पेशावर दूतावास का बंद होना एक प्रतीकात्मक कदम है जो यह बताता है कि कूटनीति अब केवल संबंधों की बात नहीं, बल्कि जोखिम प्रबंधन और रणनीतिक प्राथमिकताओं का संतुलन भी है। अमेरिका ने एक संदेश दिया है कि सुरक्षा सर्वोपरि है, और उसी के आधार पर उसकी वैश्विक उपस्थिति तय होगी।

वि चा र

फिर खुली फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल

राहुल गांधी ने असम और बंगाल चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए, जबकि पहले उन्होंने ममता बनर्जी की आलोचना की थी। लेख 'फर्जी सेक्युलरिज्म' और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को भाजपा की जीत व हिंदू ध्रुवीकरण का कारण बताता है, जिससे ममता को नुकसान हुआ।

■ राजीव सचान

पांच राज्यों के चुनावों में से राहुल गांधी को असम और बंगाल के चुनाव नतीजे स्वीकार नहीं हैं। उनके शब्दों में, 'असम और पश्चिम बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं, जहां भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चुराया है। हम ममता बनर्जी से सहमत हैं कि बंगाल में सौ से ज्यादा सीटें चुराई गईं। हमने पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह तरीका देखा है। चुनाव चोरी, संस्था चोरी-अब और चारा ही क्या है।' आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। केरलम के बारे में तो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे ने जीत हासिल की है। चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने तमिलनाडु में शानदार जीत हासिल करने वाले टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय को बधाई दी तो पराजय का सामना करने वाले स्टालिन से भी बात की।

ज्ञात हो स्टालिन ने चुनाव नतीजों को सहजता से स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से भी बात की और अपनी एक्स पोस्ट में कांग्रेस के उन लोगों को संभलने की सलाह दी, जो टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे। यह वही राहुल गांधी हैं, जिन्होंने बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले ममता को निशाने पर लेते हुए कहा था कि बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर टीएमसी में कोई न कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं मिलने वाला। ममता पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों और अपनी पार्टी के लोगों के लिए करती हैं और जनता की कोई भी मदद नहीं करतीं। उन्होंने यह भी कहा था, बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है। आखिर राहुल अपनी ही बातों को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? माना कि नेताओं की याददाश्त कुछ कमजोर होती है, पर कोई 10-12 दिन पहले की अपनी बातों को कैसे भूल सकता है? राहुल ने बंगाल में प्रचार के दौरान ही ममता को लेकर यह भी कहा था कि बंगाल में बढ़ते ध्रुवीकरण की वजह से ही भाजपा को मौका मिला। इससे इन्कार नहीं कि बंगाल में भाजपा की जीत के कई कारणों में से एक मतदाताओं का ध्रुवीकरण भी रहा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि भाजपा के पक्ष में बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता गोलबंद हुए और इसलिए भी उसे बंपर जीत मिली, पर ऐसा केवल इसलिए नहीं हुआ कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल सरीखे दल कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने का काम करते हैं। वास्तव में यह काम खुद को सेक्युलर बताने वाले अधिकतर दल करते हैं। कांग्रेस देश भर में यही करती है और बंगाल में ममता भी यही कर रही थीं और इतना खुलकर कर रही थीं कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण में बदल गया।

आम तौर पर मुस्लिम किसी दल के पक्ष में थोक वोट करते हैं और जबसे भाजपा का उभार हुआ है, तबसे वे खास तौर पर उस दल के पक्ष में वोट करते हैं, जो उसे हरा सकने में सक्षम दिखता है। इसके चलते कथित सेक्युलर दल उनकी गोलबंदी में अतिरिक्त परिश्रम करने लगे। वे उनके सामने भाजपा का हौवा खड़ा करते और उनका काम आसान हो जाता। मुस्लिम वोटों की इस गोलबंदी को ध्रुवीकरण के बजाय सेक्युलर राजनीति की संज्ञा दी जाने लगी। इस फर्जी सेक्युलर राजनीति के चलते एक समय ऐसा आया कि भाजपा विरोधी दलों के लिए मुस्लिम वोट एक तरह के वीटो पावर बन गए। जब भाजपा ने मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के जवाब में हिंदू वोटों को गोलबंदी करनी शुरू की तो उसके विरोधियों ने उस पर ध्रुवीकरण की सांप्रदायिक राजनीति करने ठप्पा लगाना शुरू किया। भाजपा ने इस ठप्पे की परवाह न करते हुए सेक्युलरिज्म को छद्म सेक्युलरिज्म की संज्ञा दी और वह उस पर इसलिए बुरी तरह चिपक गया, क्योंकि यही सच था।

नि:संदेह बंगाल में मुस्लिम वोटों के बंटवारे के कारण भी टीएमसी को नुकसान हुआ, लेकिन यदि ममता मुस्लिम समुदाय का इतना खुला तुष्टीकरण नहीं करतीं तो हिंदू भाजपा के पक्ष में खुलकर गोलबंद नहीं होते। ममता केवल इसलिए नहीं हारीं, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया और अधिसंख्य हिंदू वोट भाजपा के खाते में चले गए। वे इसलिए भी हारीं, क्योंकि उनका शासन पक्षपात और उनके नेताओं के भ्रष्टाचार संग उनकी गुंडागर्दी का पर्याय बन गया था। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी राज्य में महिला असुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बना।

ममता को घुसपैठियों की अनदेखी और मुस्लिमपरस्ती की भी कीमत चुकानी पड़ी। यही कीमत असम में कांग्रेस ने चुकाई। इस पर गौर करें कि असम में एक समय कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने वाले बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को आज की मुस्लिम लीग बता दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अब यह फ्राड बंद होना चाहिए कि मुसलमानों की गोलबंदी तो सेक्युलर राजनीति है और उसके जवाब में हिंदुओं को एकजुट करना सांप्रदायिक राजनीति। मुस्लिम वोटों ने असम और बंगाल में भी अपना वीटो पवार खो दिया और यह मिथ्या धारणा ध्वस्त हो गई कि उनके वोट किसी दल की चुनावी नैया पार लगा सकते हैं, क्योंकि उनका ध्रुवीकरण रिवर्स ध्रुवीकरण करता है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

देश/प्रदेश

अधिकारियों ने चिकित्सा संस्थानों में लिया स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा

निरीक्षण में पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज)। प्रदेश में बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव की चुनौती को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की गई है। विभाग ने हीटवेव प्रबंधन सहित स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन के दृष्टिगत राज्य स्तर से सभी जिलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर उन्हें जिलों में भेजा गया। इन अधिकारियों ने चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर हीटवेव प्रबंधन सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति का विस्तृत जायजा लिया है। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सुगमता से हो और हर रोगी को समय पर सही उपचार मिल सके। इसके दृष्टिगत हर जिले के लिए राज्य स्तर से नोडल अधिकारी बनाकर उन्हें निरीक्षण के लिए भेजा गया। इन अधिकारियों ने अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में

हीटवेव से प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। विशेष रूप से हीट-स्ट्रोक के लिए अलग से बेड आरक्षित करने, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन कूलिंग उपकरणों एवं किट्स की व्यवस्था आदि पर जोर दिया गया। इसके साथ ही मरीजों और परिजनों के लिए शीतल पेयजल, प्रतीक्षालयों में छाया एवं कूलिंग सुविधाओं की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध रहे, जिन्हें हीट-रिलेटेड बीमारियों के उपचार प्रोटोकॉल का समुचित ज्ञान हो। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

इन स्वास्थ्य सेवाओं को भी जांचा : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान केवल हीटवेव प्रबंधन ही नहीं, बल्कि फायर सेफ्टी, नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना, आईसीयू सुविधाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था मौसमी बीमारियों की रोकथाम, टीबी मुक्त भारत अभियान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की भी गहन समीक्षा की गई है। अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्यशीलता, मॉक ड्रिल, दवा स्टॉक, लैब जांच सुविधाओं एवं उपकरणों की स्थिति का भौतिक सत्यापन भी किया गया है। इसके साथ ही डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सर्विलांस गतिविधियों, आइसोलेशन वार्ड, ब्लड बैंक की तैयारियों एवं फील्ड स्तर पर एंटी-लार्वा गतिविधियों की भी समीक्षा की गई, जिससे आने वाले समय में संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

नारायणा हॉस्पिटल में 'अस्थमा क्लिनिक' का शुभारंभ

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज)। नारायणा हॉस्पिटल में विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर 'अस्थमा क्लिनिक' का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य वार्ता में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और श्वसन संबंधी बीमारियों, विशेषकर अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मरीजों को समय पर जांच, सही उपचार और जीवनशैली में सुधार के जरिए बेहतर जीवन प्रदान करना रहा। कार्यक्रम के दौरान फेफड़ों की कार्यक्षमता जांच और विशेषज्ञ परामर्श नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया। विशेषज्ञों ने अस्थमा के लक्षणों को नजरअंदाज न करने, नियमित दवा लेने और अस्थमा से होने वाले ट्रिगर्स से बचाव के महत्व को विस्तार से समझाया। इस अवसर पर डॉ. शुभम शर्मा, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी ने कहा कि अस्थमा एक नियंत्रित की जा सकने वाली बीमारी है, बशर्ते मरीज सही समय पर पहचान और उपचार शुरू करे। नियमित जांच, इनहेलर का सही उपयोग और ट्रिगर्स से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी माना जाता है। इसके माध्यम से मरीजों को एक समर्पित और समग्र देखभाल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। नारायणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर बलविंदर सिंह वालिया ने कहा कि नारायणा हेल्थ का उद्देश्य हमेशा से गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना माना जाता है। अस्थमा क्लिनिक की शुरुआत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जाती है। वहीं डॉ प्रदीप कुमार गोयल, क्लीनिकल डायरेक्टर नारायणा हॉस्पिटल जयपुर ने कहा कि आज के समय में प्रदूषण, एलर्जी और बदलती जीवनशैली के कारण अस्थमा के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। ऐसे में समर्पित क्लिनिक की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

रेलवे मुख्यालय पर संरक्षा एवं कार्य समीक्षा बैठक का आयोजन

संरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेलकर्मियों को किया पुरस्कृत

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज)। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय में बुधवार को उत्तर पश्चिम रेलवे पर संरक्षा एवं कार्य समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी विभागाध्यक्ष, चारों मंडलों के मंडल रेल प्रबन्धक वीसी के माध्यम से एवं अन्य अधिकारीगण सम्मलित हुए। बैठक में संरक्षा, कार्य निष्पादन, निर्माण कार्य, पूंजीगत आय, रेलवे ट्रैक की फेंसिंग, समपार फाटक को बंद करने, यात्री सुविधाएं तथा आय बढ़ाने इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई।

अमिताभ ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक उत्तर पश्चिम रेलवे का कार्य निष्पादन उत्कृष्ट रहा है और सामंजस्य और समन्वय के साथ कार्य कर सभी कार्यों को लक्ष्यानुसार करने पर ध्यान देना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करना है। अमिताभ ने संरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए सतर्कता और सजगता से कार्य करने पर बल दिया एवं सुरक्षित रेल संचालन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की बात कही। उन्होने गर्मियों के मौसम में ट्रैक पेट्रोलिंग के साथ साथ विद्युत व संकेत उपकरणों पर विषेश निगरानी कर समुचित मेन्टेनेंस करने के निर्देश प्रदान किए।

अमिताभ ने सभी विभागाध्यक्षों को नियमित निरीक्षण करने और संरक्षित रेल संचालन के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों की समय समय पर काउंसलिंग कर संरक्षा अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए।

आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मंत्री कुमावत

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज)। ग्राम रथ अभियान के तहत मंगलवार को पाली जिले के सुमेरपुर स्थित भांवरी में संध्या चौपाल में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीणों की पानी, बिजली, राजस्व आदि समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार द्वारा भेजे ग्राम रथ से योजनाओं की जानकारी लेकर लाभान्वित होने के लिए आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों व उपलब्धियों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि रथ का उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना है। ग्रामीणों को विकसित राजस्थान-2047 के लिए अपने सुझाव लिखकर रथ के साथ आई पेटिका में डालने की अपील की गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विकास कामों व योजनाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर चौपाल में कृषि, पशुपालन सहित अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जैविक खेती करने व सरकार की योजनाओं से आय वृद्धि करने वाले कृषकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि खेत तलाई, तारबंदी,कृषि यंत्र सहित अन्य योजनाओं के सहयोग से हमारी आय में वृद्धि हुई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवा, किसान, महिला व वृद्ध सभी के लिए कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं।

क्षेत्रीय समिति : ईपीएफओ राजस्थान की 110वीं बैठक आयोजित

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंचलिक कार्यालय, जयपुर परिसर में बुधवार को क्षेत्रीय समिति की 110वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पीसी किशन, आईएएस, शासन सचिव, श्रम, फैक्ट्री एवं बॉयलर विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की गई। क्षेत्रीय समिति की बैठक में अध्यक्ष पीसी किशन ने मृत्यु दावों के रिजेक्शन में कमी लाने एवं दावों के शीघ्रता से निष्पादन करने के निर्देश दिए तथा सभी उपस्थित सदस्यों से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ राज्य में अधिक से अधिक नियोक्ता एवं कर्मचारियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में सदस्य सचिव एवं अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान अंचल, अजीत कुमार ने संगठन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों यथा दावा निष्पादन, पेंशन, अनुपालन, वसूली, आदि में गत तिमाही में हुई प्रगति एवं राजस्थान अंचल द्वारा शुरू की गयी पहलों के बारे में अवगत कराया। बैठक में नियोक्ता प्रतिनिधि ब्रज बिहारी शर्मा, आनंद महरवाल, अशोक यादव एवं कर्मचारी प्रतिनिधि रवींद्र शुक्ला, राज बिहारी शर्मा, दीनानाथ रुंथला सहित राजस्थान अंचल के सभी क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया।